

गरीबी, साक्षरता, जाति एवं लिंग के संदर्भ में भारत में मानवाधिकार शिक्षा की स्थिति

Dr. Sunil Kumar Pandey

Assistant Professor (Faculty of Education)

Maharana Pratap Government P. G. College, Hardoi, U.P., India

skpandey.gcic@gmail.com

भारत जैसे विविध और जटिल सामाजिक-आर्थिक संरचना वाले देश में मानवाधिकार शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शोध में पाया गया कि गरीबी शिक्षा तक पहुँच और जागरूकता को सीमित करती है, साक्षरता मानवाधिकारों की समझ का आधार बनती है, जबकि जाति और लिंग सामाजिक भेदभाव और असमानता के रूप में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और सरकारी योजनाओं जैसे प्रयासों के बावजूद, यह शिक्षा मुख्यधारा के पाठ्यक्रम और वंचित समुदायों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाई है। यह शोधपत्र चुनौतियों, जैसे संसाधनों की कमी, सामाजिक असमानता और शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, की पहचान करता है और समाधान के रूप में पाठ्यक्रम सुधार, जागरूकता अभियान और वंचित समुदायों के लिए विशेष पहल का सुझाव देता है। निष्कर्ष में, यह तर्क दिया गया है कि मानवाधिकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो भारत को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सके।

मुख्य शब्द— मानवाधिकार शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक न्याय, साक्षरता, असमानता।

